जयसिंहपुरा खोर में 30 करोड़ की 4 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा

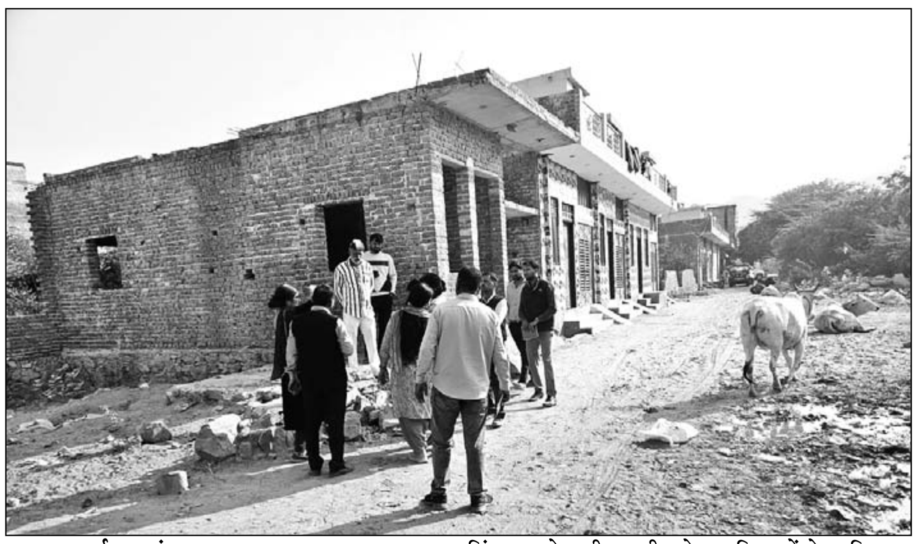

- हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में इस बेशकीमती जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, परन्तु 2 साल बाद भी हैरिटेज निगम प्रशासन नहीं जागा
- बताया जा रहा है कि जयसिंहपुरा खोर की खसरा नंबर 314/1 सरकारी भूमि पर 2011 में पीटी सर्वे कर नगर निगम द्वारा तार बाउंड्री कर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया गया था। लेकिन धीरे-धीरे भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू किया।
- वर्तमान में इस सरकारी जमीन पर दो दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया जा चुका है, वहीं खाली जमीन पर भी प्लॉट और स्कीम के नाम पर आम जनता के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर में 30 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ आम जनता ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम हेरिटेज के हवामहल-आमेर जोन स्थित वार्ड 13 के जयसिंहपुरा खोर में 4 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक दो बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण करवाकर गैर कानूनी कॉलोनी बसाई जा रही है। जहां आम जनता को सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे काट कर लाखों रुपए में मकान और प्लॉट बेचे जा रहे हैं।

दरअसल, जयसिंहपुरा खोर की खसरा नंबर 314/1 सरकारी भूमि पर 2011 में पीटी सर्वे कर नगर निगम द्वारा तार बाउंड्री कर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया गया था। लेकिन धीरे-धीरे भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। इसके बाद आज सरकारी जमीन पर दो दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया जा चुका है। वहीं खाली जमीन पर भी प्लॉट और स्कीम के नाम पर आम जनता के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता युगल किशोर भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2022 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस सरकारी जमीन से भूमाफियाओं के अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन आज लगभग 2 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है। बल्कि, हर दिन यहां अतिकर्मियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। जिस पर शासन और प्रशासन में बैठे लोगों ने आंखें बंद कर रखी है न जाने उन्हें किस बात का डर लग रहा है।

स्थानीय निवासी पप्पू लाल सैनी ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त जयसिंहपुरा खोर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी तब से अब तक यहां आधा दर्जन से ज्यादा भू माफियाओं ने मिलकर दो बीघा जमीन पर प्लाट भी काट दिए हैं वहीं शेष दो बीघा जमीन को भी हथियाना की कोशिश लगातार जारी है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के नेता इस अवैध निर्माण को हटाने की बात करते थे लेकिन आज बीजेपी की सरकार बने लगभग 1 साल का वक्त बीत गया है लेकिन किसी नेता ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की सुध तक नहीं ली है। स्थानीय पार्षद सुरेश सैनी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बन चुका है। अब तक सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दर्जनों शिकायत दे चुका हूं। लेकिन हवामहल जोन उपायुक्त सीमा चौधरी से लेकर नगर निगम कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर मैंने क्षेत्रीय विधायक बालमुकुंद आचार्य और कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव से भी शिकायत की है। जिन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसे में अगर अगले 7 दिनों में इस मामले का समाधान नहीं हुआ और नगर निगम टीम द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया। तो आम जनता के साथ मैं नगर निगम प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठूंगा।

विधायक विधानसभा की परंपराओं और मर्यादाओं का करें पालन : देवनानी

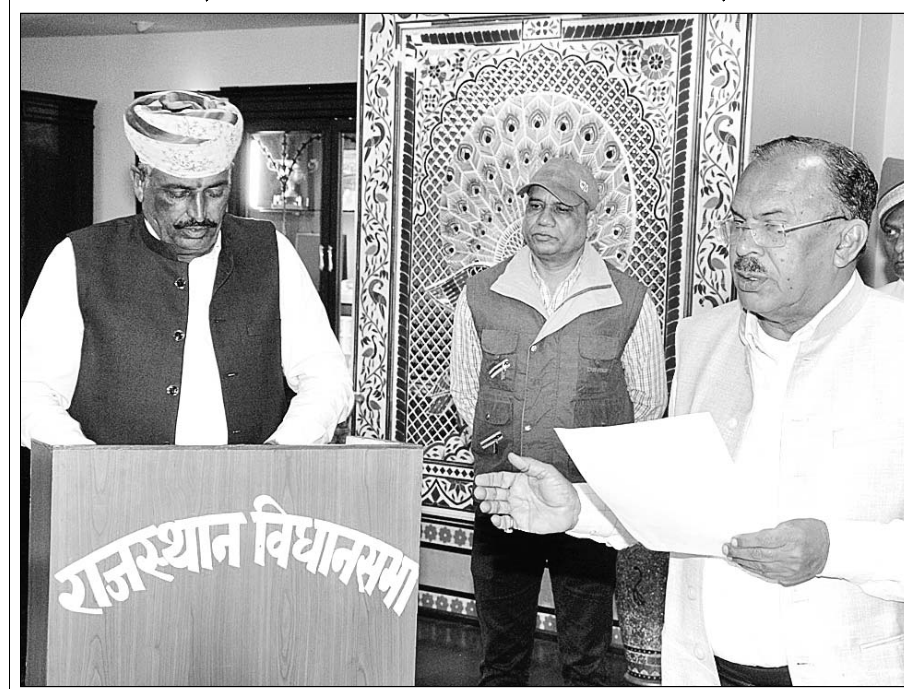

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उपचुनाव में निर्वाचित हुए सात नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित हुए सात विधायकों को अपने कक्ष में विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलायी। सभी विधायकों ने हिंदी भाषा में विधानसभा सदस्य पद की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर देवनानी ने सभी नव निर्वाचित विधायकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विधायक सदन की गौरवमयी परम्परा, गरिमा, और मर्यादा का अनुपालन करें।

समारोह में शांता अमृतलाल मीणा ने सलूंबर से, सुखवंत सिंह ने रामगढ़ से, राजेंद्र भाम्बू ने झुंझुनूं से, अनिल कुमार कटारा ने चौरासी से, रेवंतराम डांगा ने खींवसर से, राजेंद्र गुर्जर ने देवली-उनियारा से एवं दीनदयाल ने दौसा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने पर विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली।

इस अवसर पर विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग , विधानसभा में प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के के शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्र की "पी.एम. प्रणाम योजना" से आर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा : मदन राठौड़

- राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने "पीएम प्रणाम योजना" को लेकर लगाया सवाल, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने दिया जवाब

जयपुर। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार एक के बाद एक योजनाओं को शुरू कर रहे है। इसी कड़ी में "पीएम प्रणाम योजना" भी किसानों के लिए कारगर साबित तो रही है। पीएम प्रणाम योजना से जहां आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर खेती में रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी का उपयोग भी कम होगा। आर्गेनिक फसल से जहां किसानों की आय बढेगी, वहीं दूसरी ओर आमजन के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। राठौड़ ने बताया कि पीएम प्रणाम योजना को लेकर राज्यसभा में सवाल के जवाब में रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने यह जानकारी दी है।

राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को धरती के पुर्नरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) को स्वीकृति दी है। पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाना है। देश के सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया है।

राज्यसभा सांसद राठौड़ ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जैव उर्वरक और जैव समृद्ध आर्गेनिक खादों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे है।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है भारत का : तिवाड़ी

नई दिल्ली/जयपुर। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने मंगलवार को राज्यसभा में तेल क्षेत्र विधेयक 2024 के समर्थन में अपना पक्ष रखा। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि इस विधेयक में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने तथा ईंधन की खरीद को स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए ईंधन के स्त्रोतों में विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन प्रचालन की अनुमति देने तथा कम रॉयल्टी लगाने जैसे कई नीतिगत सुधार शामिल किए गए हैं। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि तेल क्षेत्र विधेयक, 2024 के मध्यम से भारत को ऊर्जा की आत्मनिर्भरता देने का लक्ष्य लिया गया है।

भाजपा की आधुनिक गुटबाजी में झगड़े से बचने के लिए संगठन चुनाव को दिया संगठन पर्व का नाम

- बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हो रहा हैं चुनाव
- नेताओं के पसंदीदा लोग बन रहे हैं अध्यक्ष

जयपुर। अंदरूनी गुटबाजी और पार्टी के झगड़ों से बचने के लिए भाजपा ने संगठन के अध्यक्षों के चुनाव को संगठन पर्व का नाम दिया है। वहीं प्रदेश भाजपा में संगठन चुनाव एक औपचारिकता बनकर रह गया हैं। जिसमे बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी चेहरे पहले से ही तय हैं। भाजपा में संगठन का चुनाव हार 3 साल में होता है लेकिन इस बार लगभग 5 साल बाद संगठन के ये चुनाव कराए जा रहे है। भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ही लाइन पर चलती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चलते संगठन के चुनाव नहीं हो पाए है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी के जून 2019 में निधन के बाद इन 5 साल में बिना संगठन चुनाव के अब तक तीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके है। जिनमें से सबसे ज्यादा लंबा तीन साल का कार्यकाल डॉ सतीश पूनिया का रहा है। पूनिया साल सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2023 तक मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष रहे। जिसके बाद बिन चुनाव के मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक यानी 1 साल 4 महीने तक चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे। जोशी के बाद 26 जुलाई 2024 को पाली जिला निवासी राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष पर मनोनीत किया गया। मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष रहते बतौर ही अब 5 साल बाद संगठन के चुनाव कराने की कवायद की जा रही है।

प्रदेशभर में सोमवार से 5 दिसंबर तक बूथ अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के 52 हजार बूथों पर अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। जिनमें से हर बूथ पर एक अध्यक्ष व 11 अन्य सदस्यों के साथ बूथ की टीम का गठन किया जाएगा। बूथ अध्यक्ष के लिए प्राथमिक सदस्य होना जरूरी है। हर बूथ पर 3 महिलाएं, 1 लाभार्थी प्रमुख, 1 वॉट्सएप प्रमुख और 1 मन की बात प्रमुख होना जरूरी है। पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से निजात पाने के लिए ही इसे संगठन पर्व का नाम दिया गया है। प्रवक्ता के अनुसार बूथ अध्यक्ष वो ही बनेगा जिस पर नेताओं का आशीर्वाद होगा। तिलोक ने बताया कि पाली जिले के 40 मंडलों के 1 हजार 682 बूथों पर अध्यक्षों का चुनाव 5 दिसंबर तक किया जाएगा। तिलोक ने बताया कि पाली जिले में 240 शक्ति केन्द्र बनाए गए है जहां एक शक्ति केन्द्र में 7 बूथ शामिल किए गए है।

प्रदेश भाजपा सूत्रों के अनुसार बिना चुनाव बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। बूथ कमेटी के गठन के समय ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख भी बनाया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार 15 जनवरी तक पक बार फिर से निर्विरोध रूप से मदन राठौड़ का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार केन्द्रीय आलाकमान ही 15 जनवरी तक पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश पार्टी अध्यक्षों के नाम पर मुहर लगाएंगे। लेकिन भाजपा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते बूथ, मंडल, और जिला अध्यक्षों के चुनाव बाद इन दो बड़े पदों के लिए नाम पर मुहर लग पाएगी।

गुजरात में आँजणा चौधरी पटेल समाज संगठन के सम्मान समारोह में शामिल हुए डॉ. पूनिया

जयपुर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया अहमदाबाद (गुजरात) प्रवास पर आँजणा चौधरी पटेल समाज संगठन, चांदखेड़ा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए।

डॉ. सतीश पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे मारवाड़ी भाई- बहन गुजरात से लेकर राजस्थान की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान वर्षों से दे रहे हैं, मारवाड़ी अपनी जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि के प्रति समर्पित होकर विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राजस्थान में दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, ऐसे में डबल इंजन भाजपा सरकार देश और राजस्थान के हित में मजबूती से कार्य कर रही हैं, प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान सहित महत्वपूर्ण योजनाएं उद्यमियों के लिए सुगम तरीके से लेकर आ रही हैं, ऐसे में मारवाड़ी अपनी जन्मभूमि की तरक्की को और अधिक मजबूती देने के लिये अपने प्रदेश में निवेश के लिए पधारें, जिनके लिए आधारभूत सुविधाओं के साथ सुखद और अनुकूल वातावरण भाजपा की भजनलाल सरकार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

आँजणा चौधरी पटेल समाज संगठन सम्मान समारोह में सतीश पूनिया, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद लुंबाराम चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे।

इसके बाद सतीश पूनिया ने अहमदाबाद पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि, शिक्षा के साथ-साथ अपने हुनर को तराशते हुये राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देने के लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करें और महापुरुषों के जीवन को आत्मसात करें।

नशा मुक्त जयपुर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित हो : कलैक्टर

- डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त अभियान के लिए ई-शपथ पोर्टल का किया शुभारंभ

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त जयपुर अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, उन्होंने मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई हो साथ ही युवाओं को नशे की लत से दूर करने और दूर रखने के लिए प्रभावी कार्ययोजना का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किये हैं।

कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलक्टर ने नशा मुक्त जयपुर की ई-शपथ की वेबसाइट को लॉन्च किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की जयपुर जिला इकाई एवं दिल्ली की टीम के सहयोग से अल्प समय में इस पोर्टल को तैयार कराया। सक्षम जयपुर अभियान के तहत जयपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए ई-शपथ पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल नशा मुक्त जयपुर के लिए वातावरण निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से जयपुर जिले के प्रत्येक युवा को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने का प्रयास रहेगा। इस हेतु 21 लाख नागरिकों को ई-शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलवाई एवं बैठक के दौरान ही अधिकारियों को ई-शपथ का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। जिला कलक्टर ने नशा मुक्त जयपुर को जन अभियान बनाने एवं युवाओं को नशे की जद में आने से बचाने के लिए सघन जागरुकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों एवं कॉलेजों के पास दवा दुकानों की जांच करने एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, तय सीमा से अधिक दवा बिक्री, बिना लाइसेंस के दवा बिक्री सहित समस्त प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार मूंड, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

डोटासरा ने जाट महासम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया

जयपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को 12 जनवरी को जयपुर में होने वाले वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल अंतरराष्ट्रीय जाट प्रतिभा सम्मान एवं जाट महासम्मेलन 2024 कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया।

महासम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि समाज के होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को जयपुर मानसरोवर के चौपड़ा फार्म पर आयोजित किया जायेगा। इस मौके कार्यक्रम में कई तरह की श्रेणी में अवार्ड दिए जाएंगे। कक्षा आठ और 10वीं में 85 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को, यूजी और पीजी में प्रत्येक कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक और पीएचडी शोधार्थी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी,पत्रकार, एंकर, सम्पादक और संवाददाता अवार्ड, वर्ष 2022-23 और 2023-24 में किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने वाले, सामाजिक, साहित्यिक,कला क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर समाज की महिलाओं की राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जायेगा और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अवार्ड दिया जाएगा। कबड्डी प्रतियोगिता में 15 से 40 उम्र तक की महिलाएं भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम विजेता टीम को 31 हजार रुपए का पुरुस्कार दिया जायेगा तथा द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 21 हजार रुपए दिए जायेंगे जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 11 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जायेगा। पोस्टर विमोचन के बाद डोटासरा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। इस मौके सामाजिक कार्यकर्ता खांगाराम, संतोष डूडी, बंशी ककरालिया आदि मौजूद थे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 12 जनवरी को जयपुर में होने वाले वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल अंतरराष्ट्रीय जाट प्रतिभा सम्मान एवं जाट महासम्मेलन 2024 कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन मंगलवार को किया।

समिट में प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की कला और कुशलता को मिलेगा उचित सम्मान

जयपुर। राजस्थान को विश्व में निवेश का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 9 से 11 दिसम्बर को राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन को सार्थक बनाने और एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शर्मा ने 10 दिन तक रोज एक नया संकल्प लेने की पहल की है।

इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को छठा संकल्प लिया कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की कला और उनकी कुशलता को उचित सम्मान मिलेगा और उनके हुनर का प्रदर्शन इस समिट का प्रमुख आकर्षण बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखरने का पर्याप्त अवसर मिले तो वे भी अपने जीवन में कौशल और योग्यता से श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बन सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि पेरिस में आयोजित पैराओलंपिक खेलों में राजस्थान की अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल तथा सुंदर गुर्जर जैसे युवाओं ने पदक जीतकर राज्य और देश का गौरव बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन को तरक्की और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराकर उनके कल्याण हेतु सतत प्रयत्नशील है।

प्लास्टिक फ्री राजस्थान के लिए किये जा रहे प्रयासों की केंद्रीय मंत्री ने सराहना की

- सफाई मित्रों के लिए 50 लाख का बीमा और शौचालय प्रोत्साहन राशि 25 हजार करने की मांग

नई दिल्ली/जयपुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटील की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, विभाग के शासन सचिव जोगाराम सहित प्रदेश के व केंद्र सरकार के विभिन्न अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में उपस्थित राजस्थान के अधिकारियों ने प्रदेश में विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जा रहे नवाचारों का प्रस्तुतीकरण केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मदन दिलावर द्वारा किए जा रहे नवाचारों को बहुत सराहा।

मंत्री ने दिलावर द्वारा प्लास्टिक फ्री राजस्थान बनाने के लिए किया जा रहे जन जागरण के प्रयासों की सराहना की और उन्हें अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणा इस्पात बताया।

दिलावर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए घर-घर से कचरा संग्रहण, कचरे का प्रथककिरण, सड़क एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक शौचालय की सफाई के लिए दरें निर्धारित की है।

इतना ही नहीं प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्य संवेदकों के माध्यम से करने की पहल की है। इस पहल के माध्यम से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तर्ज पर नियमित सफाई की व्यवस्था संचालित कर राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने हेतु प्रयासरत है।

पंचायती राज मंत्री दिलावर ने बताया कि ओडीएफ प्लस की मॉडल श्रेणी में घोषित सत्यापित गांव को उपखंड अधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जा रहा है। जिस से धरातल स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्यों की वस्तु स्थिति का आकलन किया जा सके। राजस्थान में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों की अनुपालन (सिंगल यूज प्लास्टिक को वास्तविक रूप से प्रतिबंधित करने हेतु) के लिए प्लास्टिक वेस्ट रीसायकलर्स/स्टॉकिस्ट/ संबंधित विभागों के साथ लगातार बैठकें कर इस हेतु व्यापक जन जागरण किया जा रहा है।

राजस्थान में कई जिलों में प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन हेतु अनूठे प्रयास कर रहा हैं।जिसमें घरों/ होटल/रेस्टोरेंट/संस्थाओं/ अन्य सार्वजनिक स्थलों से प्लास्टिक बोतले एकत्रित कर उनमें 50 लाख थैलियां भरकर उन्हें चबूतरा बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर स्वच्छता कर्मियों की गरिमा एवं गांव की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सफाई रथ का उपयोग किया जा रहा है।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की समक्ष विभिन्न समस्याओं और मांगों को भी उठाया। दिलावर ने मांग की कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सफाई मित्रों हेतु 50 लख रुपए तक का बीमा की व्यवस्था की जाए। व्यक्तिगत शौचालय हेतु लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 12000 रुपये का प्रावधान है।